प्राइस कंट्रोल के बाद शुगर मिलों के सामने एक और मुश्किल

[जयश्री भोसले | पुणे]

चीनी की कीमत पर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद बाय-प्रॉडक्ट्स से भी शुगर मिलों की इनकम कम होने लगी है। जब 1 दिसंबर से पेराई शुरू होगी, तो महाराष्ट्र के नए को-जेनरेशन शुगर प्लांट्स शायद गन्ने के अवशेष से पैदा हुई रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को बेच नहीं पाएं।

दरअसल, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने इस सिलसिले में पावर परचेज एग्रीमेंट्स (पीपीए) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इन प्लांट्स में तकरीबन 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। चीनी मिलों के मुनाफे में शुगर प्रॉडक्शन से जुड़े बाय-प्रॉडक्ट्स काफी अहम होते हैं, क्योंकि गन्ने और शुगर की कीमत पर सरकार का नियंत्रण होता है। हाल में केंद्र सरकार ने एथनॉल पर फिर से एक्साइज ड्यूटी लगाई है। इससे मिलों की कमाई में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती हुई है।

महाराष्ट्र ने हमेशा शुगर को-जेनरेशन प्लांट्स द्वारा पैदा की गई बिजलों के लिए सबसे ज्यादा टैरिफ का भुगतान किया, जिससे इसकी ग्रोथ काफी तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 1 अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान 6.70 रुपये के टैरिफ रेट को मंजूरी दी है। हालांकि, MSEDCL ने नई को-जेनरेशन यूनिट्स के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से मना कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, एमएसईडीसीएल का कहना है कि उसके पास सप्लाई के लिए पहले से पर्याप्त बिजली है। महाराष्ट्र की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लॉस में है, लिहाजा वह महंगी बिजली खरीदने को लेकर इच्छुक नहीं है।

महाराष्ट्र के को-जेनरेशन शुगर प्लांट्स के लिए गन्ने के अवशेष से पैदा हुई रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बेचना हो सकता है मुश्किल